मिग क्रिकेट क्लब

बनाम

अभिनव सहकार शिक्षा समाज और ओआरएस।

(2007 की सिविल अपील सं. 2047)

5 सितंबर, 2011

[मार्कंडेय काटजू और चंद्रमौली के. आर.प्रसाद, जे. जे.]

महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना अधिनियम, 1966: एसएस। 31 (1), 37 (2) - विकास योजना के मसौदे को मंजूरी-आयोजितः लागू होने से पहले मौजूद विकास योजना अधिनियम को स्वीकृत विकास माना जाएगा। योजना यू / अधिनियम की धारा 31 (1)-तत्काल मामले में, विकास अधिनियम के प्रारंभ से पहले मौजूद योजना से पता चलता है "खेल के मैदान" के लिए आरक्षित क्षेत्र जिसे राज्य सरकार द्वारा "स्कूल और सांस्कृतिक समाज" में संशोधित किया गया था "स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र "25 अप्रैल की अधिसूचना द्वारा, 1985- 24 अप्रैल, 1992 की कानून अधिसूचना के तहत इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति थी, बशर्ते कि राज्य यू/द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार धारा 31 (1) ने भूमि के उपयोगकर्ता को "खेल का मैदान" में संशोधित किया था-यह नहीं था विकास योजना में संशोधन लेकिन इसकी मंजूरी शक्ति के प्रयोग में यू / अधिनियम की धारा 31 (1)-उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल की अधिसूचना

पर विचार करके खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया, 1985 विकास योजना की मंजूरी यू / धारा 37 (2) अधिनियम और 24 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना अंतिम विकास योजना का संशोधन जिसने इसके आदेश को अवैध बना दिया।

प्रशासनिक कानूनः न्यायिक समीक्षा-के उपयोगकर्ता में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा भूमि-न्यायिक समीक्षा का दायरा-आयोजितः भूमि के उपयोगकर्ता का निर्णय अधिकार प्राप्त प्राधिकारी द्वारा किया जाना है। ऐसा निर्णय लेना और न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करना न्यायिक समीक्षा उसी में हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि उपयोगकर्ता में परिवर्तन मनमाना पाया जाता है-नगर नियोजन के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और यह सबसे अच्छा है राज्य सरकार का निर्णय जिसके लिए विशेषज्ञ निकाय की सलाह उपलब्ध है, नगर नियोजन।

विधियों की व्याख्याः कानूनी कल्पना-आयोजितः जब ए. कानूनी कल्पना बनाई जाती है, इसे पूरा प्रभाव दिया जाएगा-आम तौर पर कानूनी कल्पना सार्वजनिक नीति को आगे बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानते हैं और इसमें शामिल होते हैं उस स्थिति के प्राकृतिक परिणाम।

प्रत्यर्थी का मामला सं। 1 कि यह दिया गया था 99 वर्ष की अवधि के लिए भूमि के एक हिस्से का पट्टा महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास

प्राधिकरण (एमएचएडीए) और बॉम्बे आवास और क्षेत्र विकास बोर्ड (बीएचएडीबी) ने नगर निगम की सहमति से ग्रेटर बॉम्बे निगम (निगम)। जब उत्तरदाता नं. 1 विद्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव

उस पर, यह देखा गया कि विचाराधीन क्षेत्र विकास योजना के मसौदे में एक खेल के मैदान के लिए आरक्षित था। उत्तरदाता नं. 1 इस तथ्य को एमएचएडीए के ध्यान में लाया और बी. एच. ए. डी. बी. और जवाब में उत्तरदाता नं. 1 कानून के अनुसार भूमि के उपयोगकर्ता को बदलने के लिए कहा गया था। इस बीच, महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना अधिनियम, 1966 20.12.1966 पर लागू हुआ। फरवरी, 1984 में निगम ने उपयोगकर्ता को मंजूरी देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया स्कूल के निर्माण के उद्देश्य से कहा गया भूखंड। के द्वारा अधिसूचना दिनांक 25.4.1985, उक्त भूमि को निर्धारित किया गया था विकास योजना में विद्यालय और सांस्कृतिक केंद्र के लिए क्षेत्र से। 1985-86 अवधि के दौरान, अपीलकर्ता-क्लब ने उपयोगकर्ता को बदलने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया "क्रिकेट खेल के मैदान" के लिए उक्त भूखंड। प्रत्यर्थी को नहीं समझाने का प्रयास किया गया। 1 विद्यालय को स्थानांतरित करना एक अन्य भूखंड के रूप में विचाराधीन भूखंड की अपीलार्थी द्वारा उसके खेल के मैदान के लिए आवश्यकता थी। उत्तरदाता नं. 1 नहीं किया प्रस्ताव को स्वीकार करें और 10.11.1986 दिनांकित पत्र द्वारा MIG CRICKET CLUB v. की मांग की। अभिनव सहकार शिक्षा 143 समाज के कारण

एक परिसर की दीवार बनाने की अनुमति अपीलार्थी द्वारा दी गई धमकियाँ। उत्तरदाता नं. 1 राज्य सरकार को विकास योजना प्रस्तुत की। अधिनियम की धारा 31 (1) ने भूमि के उपयोगकर्ता को संशोधित किया था। प्रश्न में और इसके बजाय भूमि के लिए आरक्षित दिखाया जा रहा है " स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र ", इसे खेल के मैदान के रूप में दिखाया गया था। उत्तरदाता नं. 1 एक रिट याचिका दायर की अधिसूचना को चुनौती देना और आगे एक निर्देश के लिए उत्तरदाताओं को "स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र" के लिए भूखंड के आरक्षण को बहाल करने के लिए। उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया अधिसूचना दिनांक 24.4.1992 में कहा गया है कि इसे जारी किया गया था दिनांकित 10.4.1985 अधिसूचना पर विचार किए बिना जिसने उसी को अवैध बना दिया। तत्काल अपील उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1. धारा 35 का एक सादा पाठ महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम से पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विकास योजना अधिनियम के प्रारंभ से पहले, माना जाएगा अधिनियम के तहत स्वीकृत एक अंतिम विकास योजना होना। विकास योजना बनाने के लिए विचार करने की आवश्यकता है -विभिन्न निवेश और उसके लिए, कई निकायों को होना चाहिए अधिनियम में दिए गए परामर्श और विभिन्न कदम हैं -लेने की जरूरत है। स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ समय लगेगा।

विकास योजना के बिना एक शहर का अस्तित्व नहीं हो सकता है, अन्यथा यह अराजकता का कारण बन सकता है। कोई विकास योजना नहीं 20 दिसंबर, 1966 को लागू हुए अधिनियम के तहत बनाया गया था और इसलिए विधायिका ने एक अधिनियम की धारा 35 को लागू करके कानूनी कल्पना। यह प्रदान किया गया एक तथ्य मान लेने के लिए अर्थात एक विकास योजना का अस्तित्व, जो वास्तव में 144 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2011] 11 एस. सी. आर. के अनुसार नहीं बनाया गया था।अधिनियम के प्रावधान। जब एक कानूनी कल्पना बनाई जाती है, तो यह पूर्ण प्रभाव दिया जाएगा। आम तौर पर कानूनी कल्पना सार्वजनिक नीति को आगे बढ़ाने और लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। कुछ व्यक्ति और संस्थान। कानूनी कल्पना की प्रवृत्ति होती है एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानते हैं और उस स्थिति के प्राकृतिक परिणाम को शामिल करते हैं। इसलिए, विकास योजना, जो लागू होने से पहले मौजूद थी पूरा क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए अलग से बिना किसी संशोधन के या ऐसे संशोधनों के अधीन जो वह उचित समझे। अधिनियम की योजना के तहत, राज्य द्वारा विकास योजना में एक छोटा सा संशोधन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार प्रदान की जाती है अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत। [पारस 11,12] [153-एफ-एच; 154-ए-डी; 155-सी-डी]

1.2. अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विकास योजना अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, यह अंतिम हो गया है अधिनियम के तहत विकास योजना। विकास योजना अधिनियम के प्रारंभ से पहले मौजूद कि विचाराधीन क्षेत्र "खेल के मैदान" के लिए आरक्षित था जिसे "स्कूल और सांस्कृतिक समाज" में संशोधित किया गया था अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग और द्वारा "विद्यालय और सांस्कृतिक केंद्र" के लिए निर्धारित कानून के तहत अनुमत। यह प्रतिवादी की याचिका थी नं. 1 कि निगम ने सूचित किया कि प्रस्तावित में विचाराधीन क्षेत्र की विकास योजना "क्रिकेट क्लब और खेल का मैदान" के रूप में दिखाया गया है। 25 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना को अंतिम मंजूरी दी गई थी विकास योजना, विचाराधीन क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए विकास योजना के मसौदे को प्रस्तुत किया गया राज्य सरकार। राज्य मिग क्रिकेट क्लब v को प्रस्तुत मसौदा योजना। अभिनव सहकार शिक्षा 145 समाज सरकार ने इस पर विचार किया और विकास 24 अप्रैल, 1992 की योजना को मंजूरी दी गई थी। यह नहीं था। विकास योजना में संशोधन लेकिन इसकी मंजूरी धारा 31 (1) के तहत शक्ति के प्रयोग में समान अधिनियम। उच्च न्यायालय ने विचार करके खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना को मंजूरी दी जाएगी। अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत विकास योजना और 24 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना अंतिम विकास योजना का संशोधन जिसने

अपने आदेश को अवैध बना दिया। यह सामान्य बात है कि इसकी वैधता आदेश में उल्लिखित धारा पर निर्भर नहीं करता है आदेश दें। आदेश में ही उल्लिखित गलत प्रावधान आदेश को अमान्य नहीं करता है, यदि यह पाया जाता है कि आदेश कर सकता है एक मामला, तत्काल की तरह, जो था उसके विपरीत अधिसूचना में उल्लिखित न्यायालय यह नहीं कह सकता कि अधिसूचना देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया था यदि वास्तव में ऐसी शक्ति मौजूद है तो अवैध है। [पैरा 13] [156-सी-एच; 157 ए-बी]

2. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि भूमि का उपयोगकर्ता होना है ऐसा लेने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया निर्णय और यह न्यायालय अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए समीक्षा उसी में हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि उपयोगकर्ता में परिवर्तन मनमाना पाया गया है। प्रक्रिया. प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करना शामिल है और वर्तमान और भविष्य में निवासियों की आवश्यकताएँ ताकि उनके जीवन को खुशहाल, स्वस्थ और आरामदायक बनाया जा सके।

नगर नियोजन के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और राज्य सरकार के निर्णय पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। विशेषज्ञ निकाय की सलाह उपलब्ध है। तथ्यों में तत्काल मामले में, शक्ति

का प्रयोग किया गया था कानून के अनुसार और इसमें कोई मनमानी नहीं है एक ही। [पैरा 14] [157-सी-ई]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 2047/2007।

उच्च न्यायालय बॉम्बे 1992 की रिट याचिका संख्या 1561 के निर्णय और आदेश दिनांक 05.09.2005 से।

के साथ

कोंम्ट। पेट। (ग) 2007 की सं. 43।

श्याम दीवान, अतुल वाई. चिताले, आर. पी. भट्ट, जय सावला, एस. घाणेकर, राजेश कोठारी, रेणुका साहू, मीनाक्षी ओग्रा, वैशाली थोराट, करण थोराट, ए. एस. भास्मे, पंकज मिश्रा,

निष्ठा कुमार, सुचित्रा अतुल चिताले, संजय खार्डे (आशा के लिए)

गोपालन नायर) महिमा सी. श्रॉफ, चिराग एम. श्रॉफ, विनय

नवारे, केशव रंजन (आभा आर. शर्मा के लिए) पार्टियाँ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बंबई उच्च न्यायालय ने दिनांक 5 सितंबर, 2005 को पारित किया 1992 की रिट याचिका संख्या 1561 जिसके तहत उसने रिट याचिका की अनुमति दी थी और 24 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जो मई, 1992 को राजपत्र में 7 तारीख को प्रकाशित हुई थी और

आगे रिट याचिका के उत्तरदाताओं को पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया "विद्यालय और सांस्कृतिक केंद्र" के लिए भूखंड का आरक्षण।

2. रिट याचिकाकर्ता के अनुसार-प्रतिवादी संख्या 1 अभिनव सहकार एजुकेशन सोसाइटी, के तहत पंजीकृत एक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) "रिट याचिकाकर्ता") को 7224 वर्ग किलोमीटर के भूखंड का एक हिस्सा आवंटित किया गया था। यार्ड, जिसमें सर्वेक्षण संख्या 341 स्थित है मुंबई शहर में एम. आई. जी. कॉलोनी, गांधी नगर, बांद्रा (पूर्व) में। प्रत्यर्थी संख्या 4, महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (इसके बाद "म्हाडा" के रूप में संदर्भित) और प्रत्यर्थी संख्या 5, बॉम्बे आवास और क्षेत्र विकास बोर्ड (इसके बाद "बी. एच. ए. डी. बी". के रूप में संदर्भित) प्रत्यर्थी संख्या 3, एम. आई. जी. क्रिकेट क्लब के नगर निगम v की सहमति।

अभिनव सहकार शिक्षा 147 समाज [चंद्रमौली के. आर.। प्रसाद, जे।]

ग्रेटर बॉम्बे (इसके बाद "निगम" के रूप में संदर्भित)

फरवरी, 1965 के एक प्रस्ताव के तहत एक अवधि के लिए पट्टा दिया गया के समतुल्य प्रीमियम पर रिट याचिकाकर्ता को 99 वर्ष का किश्तों के माध्यम से वार्षिक रूप से निर्धारित और देय मूल्य। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, हालांकि, भूखंड की माप पर, क्षेत्र 7301.25 वर्ग मीटर पाया गया। यार्ड और जब इसने उस पर एक स्कूल भवन बनाने का

प्रस्ताव रखा, तो यह आया इसकी सूचना है कि विचाराधीन क्षेत्र को विकास योजना के मसौदे में खेल के मैदान के लिए आरक्षित किया गया है। लेखन याचिकाकर्ता लाया गया यह तथ्य एम. एच. ए. डी. ए. और बी. एच. ए. डी. बी. को दिनांकित पत्र द्वारा सूचित किया गया है

8 मई, 1968 और उसके जवाब में रिट याचिकाकर्ता सोसायटी को भूमि के उपयोगकर्ता को बदलने के लिए कहा गया था। कानून के अनुसार। इस बीच, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना अधिनियम, 1966 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) लागू हुआ था 20 दिसंबर, 1966।

3. रिट याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि 15 नवंबर, 1978 के पत्र द्वारा सरकार के सचिव आवास विभाग में महाराष्ट्र और प्रमुख

म्हाडा के कार्यकारी अधिकारी और उपाध्यक्ष ने एक पत्र मे शहरी विकास विभाग के सचिव को संबोधित विकास योजना के मसौदे में संशोधन का अनुरोध उक्त प्लॉट के उपयोगकर्ता के लिए "स्कूल का उद्देश्य" दिखाना। 1 जनवरी, 1979 के पत्र द्वारा, के वरिष्ठ नगर योजनाकार बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिट याचिकाकर्ता को कुछ विवरण और योजनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। के अनुसार रिट याचिकाकर्ता को उन्होंने निर्देश का विधिवत पालन किया। इसमें है।आगे

कहा गया कि 12 नवंबर, 1979 के पत्र द्वारा स्कूल के उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोगकर्ता। दिनांकित पत्र द्वारा 10 अगस्त, 1983 में राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग के अवर सचिव ने सूचित किया कि रिट याचिकाकर्ता कि निर्देश जारी किया गया है प्लॉट के उपयोगकर्ता के परिवर्तन के लिए निगम विद्यालय के उद्देश्य। फरवरी 1984 में, रिट 148 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2011] 11 एस. सी. आर. के अनुसार। में "स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र" के लिए निर्धारित क्षेत्र की विकास योजना। उपयोगकर्ता का परिवर्तन निगम द्वारा 15 अप्रैल, 1985 के पत्र द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर योजना (प्रभाग योजना) द्वारा रिट याचिकाकर्ता को उक्त भूखंड की पुष्टि भी की गई थी।

4. यह रिट याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस दौरान अवधि 1985-1986 यह उसके संज्ञान में आया कि रिट याचिका के प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात एम. आई. जी. क्रिकेट क्लब (इसमें अपीलकर्ता) परिवर्तन के लिए राज्य सरकार से भी संपर्क किया था "क्रिकेट खेल के मैदान" के लिए उक्त भूखंड का उपयोगकर्ता। यह रिट याचिकाकर्ता का मामला है कि उसे स्कूल को दूसरे भूखंड में स्थानांतरित करने के लिए मनाने का प्रयास किया गया था क्योंकि विचाराधीन भूखंड की आवश्यकता थी अपने खेल के मैदान के लिए एम. आई. जी. क्रिकेट क्लब (इसके बाद "द क्लब" के रूप में संदर्भित) द्वारा। याचिकाकर्ता दबाव के आगे नहीं झुकी और दिनांक 10 नवंबर, 1986 के पत्र द्वारा अनुमति मांगी गई क्लब द्वारा दी गई

धमकियों के कारण एक परिसर की दीवार खड़ी करें। निगम ने 24 तारीख को अपने संचार द्वारा नवंबर, 1986 ने मांगी गई अनुमति दी और सूचित किया राज्य को विकास योजना प्रस्तुत करने के लिए रिट याचिकाकर्ता सरकार। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, निगम यह सूचित किया गया कि सरकार को प्रस्तुत प्रस्तावित विकास योजना में गलती से इस भूखंड को "क्रिकेट क्लब और खेल का मैदान" के रूप में दिखाया गया है। उपरोक्त परिसर में याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से संपर्क करने के लिए कहा गया था गलती ठीक हो गई। जैसा कि निर्देश दिया गया है, याचिकाकर्ता 8 वें पत्र द्वारा दिनांक नवंबर, 1986 को राज्य सरकार से संपर्क किया गया गलती के सुधार के लिए और वही था निगम द्वारा यह कहते हुए स्वीकार किया गया कि उपयुक्त मिग क्रिकेट क्लब v. अभिनव सहकार शिक्षा 149 समाज (चंद्रमौली के. आर.) प्रसाद, जे।]

इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, याचिकाकर्ता को आश्चर्य हुआ कि 24 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना 7 मई, 1992 को राजपत्र में प्रकाशित हुई, जिसमें पता चला कि राज्य सरकार शक्तियों का प्रयोग कर रही है।

अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत प्रदत्त, भूमि के उपयोगकर्ता को संशोधित किया गया था और भूमि दिखाने के बजाय

"स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र" के लिए आरक्षित इसे एक के रूप में दिखाया गया था " खेल का मैदान "।

5. उसी से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका को प्राथमिकता दी और इसके अलावा, रिट याचिका के उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए "विद्यालय और सांस्कृतिक केंद्र" के लिए भूखंड के आरक्षण को बहाल करना।

6. क्लब सहित रिट याचिका में उत्तरदाताओं, यहाँ अपीलार्थी ने रिट याचिका का विरोध किया और के अनुसार 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना मामूली थी। भूमि के किसी विशिष्ट भूखंड के संबंध में संशोधन राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत विकास योजना अधिनियम का प्रारंभ। यह भी बताया गया कि पूरे क्षेत्र के लिए विकास योजना का मसौदा पहले ही 16 अक्टूबर, 1984 को तैयार किया जा चुका था और आवश्यक आपत्तियों और सुझावों को सुनने के बाद संशोधित मसौदा तैयार किया गया था विकास योजना 29 अप्रैल, 1986 को निगम द्वारा राज्य को आवश्यक संशोधन के साथ प्रस्तुत की गई थी। सरकार। उसी को अंतिम रूप दिया गया और विवादित 24 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना जारी और प्रकाशित की गई थी। 7 मई, 1992 को, जिसके तहत विचाराधीन भूमि को दिखाया गया था जैसा कि "खेल के मैदान" के उद्देश्य के लिए आरक्षित है। यह

आगे कहा गया है प्रत्यर्थियों द्वारा कहा गया कि याचिकाकर्ता के हितों की भी रक्षा करने के लिए पूर्व की ओर एक भूखंड आरक्षित किया गया था "स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र" के लिए विचाराधीन भूखंड का हिस्सा। उत्तरदाताओं के अनुसार योजना को अंतिम रूप दिया गया था सभी इच्छुक पक्षों को सुनने के बाद किया गया। यह है आरोप उत्तरदाताओं का कहना है कि याचिकाकर्ता द्वारा खोला गया स्कूल 1990 से स्थायी रूप से बंद था और विफलता के कारण याचिकाकर्ता की ओर से 150 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2011] 11 एस. सी. आर. को देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। एम. एच. ए. डी. ए., याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन रद्द होने योग्य है। उत्तरदाताओं ने आगे कहा है कि भूमि में प्रश्न निगम को दिया गया था जो बदले में पट्टे पर दिया गया था सितंबर, 1974 से क्लब के लिए भी ऐसा ही है।

7. पक्षकारों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या 24 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना जारी की गई अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत शक्तियां कानूनी, वैध और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करती थीं।

8. सामग्री के मूल्यांकन पर उच्च न्यायालय आया यह निष्कर्ष कि 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना धारा के तहत शक्तियों के प्रयोग में कथित रूप से जारी किया गया 37 (2) वास्तव में अधिनियम की धारा 31

(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। ऐसा करते हुए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" तथ्य यह है कि विकास योजना का मसौदा तैयार किया गया था और आपत्तियों और सुझावों के लिए रखा गया जनता के सदस्यों ने 30 अप्रैल, 1984 को और उसके बाद 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना द्वारा उत्तरदाताओं को विचाराधीन भूमि के आरक्षण को अंतिम रूप दिया था स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र के लिए, भले ही इसके चेहरे पर अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 37 (2) तहत शक्तियों के प्रयोग को संदर्भित करती है, सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए, यह में जारी किया गया है के रूप में समझा जाना होगा उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत शक्तियों का प्रयोग संबंधित क्षेत्र के संबंध में। यह ध्यान देने योग्य है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि विकास योजना के मसौदे के बाद 30 अप्रैल, 1984 को तैयार किया गया था 10 अप्रैल की अधिसूचना के अलावा उक्त अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में उक्त योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, 1985. ऐसा होने के कारण, कोई अवसर नहीं था धारा 37 (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 10 अप्रैल, 1985 को उत्तरदाता जो स्पष्ट रूप से संशोधन की बात करते हैं अंतिम विकास योजना में "। मिग क्रिकेट क्लब v.

अभिनव सहकार शिक्षा 151 समाज [चंद्रमौली के. आर.। प्रसाद जे. जे अप्रैल, 1992 की अधिसूचना के संबंध में कहा गया है कि - अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं उच्च न्यायालय ने कहा कि वास्तव में राज्य सरकार ने धारा 37 (2) तहत शक्ति का प्रयोग किया एक्ट करें। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> ..... एक बार यह उत्तरदाताओं को पता चला कि मसौदा योजना 30 अप्रैल, 1984 को तैयार की गई थी और इसके अधीन थी। सदस्यों की आपत्तियों और सुझावों पर सार्वजनिक और उसके बाद 10 अप्रैल, 1985 को, इस तरह का एक हिस्सा उक्त अधिनियम की धारा 37 (2) की अधिसूचना जारी नहीं की जा सकी इसका अर्थ यह हुआ कि शक्तियाँ वास्तव में थीं, धारा 37 (2) के तहत प्रयोग किया गया। इसका अर्थ निकालना होगा जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत प्रयोग किया गया था, और इसी कारण से, यह आवश्यक था उत्तरदाताओं को यह समझाने के लिए कि कैसे और क्यों कहा गया 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना पर विचार नहीं किया जा सका या जारी करते समय इसका अर्थ लगाना आवश्यक नहीं था। अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल,1992"। अंततः उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 24 अप्रैल, 1992 अधिसूचना 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना पर विचार किए बिना

जारी की गई थी, जो इसे अवैध बनाती है। ऐसा मानते हुए उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

..... विवादित अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल की है। 1992. ऐसा होने के कारण, एक बार यह माना जाता है कि आक्षेपित इसके अनुपालन में अधिसूचना जारी नहीं की गई है कानून के प्रावधान और उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया मामला याचिकाकर्ता को मामले में सुनवाई के अवसर और मामले पर विचार करने के अवसर का खुलासा नहीं करता है। 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना और विवादित अधिसूचना जारी करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा दिमाग का उपयोग अधिसूचना, ऊपर बताए गए कारणों के लिए, इसलिए, आक्षेपित अधिसूचना को रद्द किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2011] 11 एस. सी. आर. को अलग रखा जा सकता है। 152 जिस हद तक यह विचाराधीन कथानक से संबंधित है। नतीजतन, उत्तरदाताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए भी निर्देशित करना होगा 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना के अनुसार विचाराधीन भूखंड का आरक्षण। तदनुसार उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुमति दी, विवादित अधिसूचना को रद्द

कर दिया और रिट याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत प्रदान कर दी।

9. श्री श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो उनकी ओर से पेश हुए अपीलार्थी का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित करने में गलती की 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना वास्तव में अंतिम है। विचाराधीन क्षेत्र के संबंध में विकास योजना अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत विचार किया गया। वह बताते हैं कि अधिनियम की धारा 35 के तहत एक विकास योजना द्वारा स्वीकृत अधिनियम के प्रारंभ से पहले राज्य सरकार अधिनियम के लागू होने से पहले अस्तित्व। इसके तहत मानित विकास योजना, श्री दीवान के अनुसार, विचाराधीन क्षेत्र को "खेल का मैदान" के रूप में दिखाया गया था और इसलिए, अंतिम विकास योजना में संशोधन किया जा सकता है अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग। वास्तव में, 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना जारी करते समय,एक शक्ति का प्रयोग किया गया था जो अधिसूचना से स्पष्ट होगा और "खेल के मैदान" के लिए आरक्षित स्थान था "स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र" के लिए निर्धारित। श्री दीवान आगे इंगित करता है कि विकास योजना का मसौदा 29 तारीख को प्रस्तुत किया गया था 24 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना द्वारा अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत विकास योजना के रूप में अप्रैल, 1986 को मंजूरी दी गई थी और अधिसूचना से ही पता चलता है कि इसे अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत मंजूरी दी गई थी।

उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने गलती से कहा कि यह अधिसूचना, वास्तव में, धारा के तहत जारी की गई थी 37 (2) अधिनियम से। श्री दीवान के अनुसार, कुल मिलाकर 10 अप्रैल, 1984 और 24 अप्रैल, 1992 की अधिसूचनाएँ। यह दर्शाता है कि यह मिग क्रिकेट क्लब v के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। अधिनियम की धारा 37 (2) और धारा 31 (1), लेकिन उच्च न्यायालय स्वयं को गलत तरीके से निर्देशित किया और इसे अधिनियम की धारा 31 (1) और 37 (2) के तहत जारी किया गया।

10. सुश्री वैशाली थोराट, हालांकि, की ओर से पेश हुईं प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रस्तुत करता है कि 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना धारा के तहत स्वीकृत एक अंतिम विकास योजना थी 31 (1) अधिनियम का और उसी पर विचार किए बिना यह किया गया है 24 अप्रैल, 1992 की विवादित अधिसूचना द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जो कानून की नजर में इसे अवैध बनाता है। वह आगे इशारा करती है 10 अप्रैल 1985 की अधिसूचना पर विचार न करने पर, 24 अप्रैल, 1992 को अधिसूचना जारी करते समय आक्षेपित अधिसूचना को दूषित करता है।

11. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की जांच आवश्यक है अधिनियम की योजना। अधिनियम की धारा 35 जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" 35. राज्य द्वारा स्वीकृत विकास योजनाएं

यदि किसी योजना प्राधिकरण ने एक विकास योजना तैयार की है जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले, तो ऐसे विकास योजना को अंतिम माना जाएगा। इस अधिनियम के तहत स्वीकृत विकास योजना।

उपरोक्त प्रावधान के सरल अध्ययन से, यह है - यह स्पष्ट है कि राज्य द्वारा स्वीकृत विकास योजना अधिनियम के प्रारंभ से पहले सरकार, के तहत स्वीकृत एक अंतिम विकास योजना मानी जाती है एक्ट करें। विकास योजना बनाने के लिए विभिन्न आदानों पर विचार करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए कई निकायों से परामर्श करना पड़ता है। और अधिनियम में दिए गए विभिन्न कदमों की आवश्यकता है लिया गया। स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ समय लगेगा। विकास योजना के बिना एक शहर का अस्तित्व नहीं हो सकता है, अन्यथा यह अराजकता का कारण बन सकता है आए अधिनियम के तहत कोई विकास योजना नहीं बनाई गई थी 20 दिसंबर, 1966 को लागू किया गया और इसलिए विधायिका ने अधिनियम की धारा 35 को लागू करके एक कानूनी कल्पना

का निर्माण किया। यह एक तथ्य मान लेने के लिए प्रदान किया गया है अर्थात एक विकास योजना का अस्तित्व, जो वास्तव में, के अनुसार नहीं बनाया गया था अधिनियम के प्रावधान। यह ध्यान में रखना होगा कि जब कोई कानूनी कल्पना बनाई जाती है तो उसे पूरा प्रभाव दिया जाएगा। आम तौर पर कानूनी कल्पना सार्वजनिक नीति को आगे बढ़ाने और इसे संरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। कुछ व्यक्तियों और संस्थानों के अधिकार। कानूनी कथा एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानती है और इसमें शामिल है उस स्थिति के प्राकृतिक परिणाम। इसलिए,अधिनियम के लागू होने से पहले मौजूद विकास योजना को स्वीकृत विकास योजना माना जाएगा। अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत।

12. अधिनियम की धारा 31 (1) अन्य बातों के साथ-साथ मंजूरी का प्रावधान करती है। विकास योजना के मसौदे का विवरण इस प्रकार हैः

" 31. विकास योजना के मसौदे को मंजूरी।

(1) इस धारा के प्रावधानों के अधीन, और बाद में नहीं योजना प्राधिकरण से ऐसी योजना की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष से अधिक, या, जैसा भी मामला हो, उक्त अधिकारी, राज्य सरकार, नगर योजना निदेशक से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक में अधिसूचना जारी कर सकती है। या तो बिना संशोधन के, या ऐसे संशोधनों के अधीन जो वह उचित समझे, या विकास मसौदे को वापस कर दे योजना प्राधिकरण या, जैसा भी मामला

हो, उक्त अधिकारी को योजना को संशोधित करने के लिए योजना, जैसा कि वह निर्देश दे सकता है, या मंजूरी देने से इनकार करना और योजना प्राधिकरण को निर्देश देना या एक नई विकास योजना तैयार करने के लिए उक्त अधिकारीः

बशर्ते कि, राज्य सरकार, यदि वह उचित समझती है, चाहे उक्त अवधि समाप्त हो गई हो या नहीं, से बढ़ा सकती है समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, विकास योजना या मिग क्रिकेट क्लब के मसौदे को मंजूरी देने की अवधि v. उस पर मंजूरी देने से इनकार करना, ऐसी आगे की अवधि तक जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता हैः

बशर्ते कि, जहां संशोधन किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक पर्याप्त प्रकृति, राज्य सरकार एक प्रकाशित करेगी आधिकारिक राजपत्र में और स्थानीय समाचार पत्रों में भी सूचना किसी भी व्यक्ति से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करना एक अवधि के भीतर प्रस्तावित संशोधनों का सम्मान इस तरह की सूचना की तारीख से साठ दिन।

उपरोक्त प्रावधान राज्य को शक्ति प्रदान करता है। सरकार प्रस्तुत विकास योजना के मसौदे को मंजूरी देगी इसे पूरे क्षेत्र के लिए या अलग से इसके किसी भी हिस्से के लिए बिना किसी संशोधन के या ऐसे संशोधनों के अधीन जो हो सके उचित सोचें। इसलिए, अधिनियम की धारा 31 राज्य

सरकार की मंजूरी देने की शक्ति के क्षेत्र में काम करती है विकास योजना का मसौदा। अधिनियम की योजना के तहत, धारा के तहत स्वीकृत विकास योजना का एक छोटा सा संशोधन 31 (1) अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत प्रावधान किया गया है। यह इस प्रकार पढ़ता हैः

" 37. अंतिम विकास योजना में मामूली संशोधन।

(1) XX XX XX

(2) जो व्यक्तियों को सुनने के बाद आवश्यक लगे सूचना के साथ और निदेशक से परामर्श करने के बाद ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उचित समझे या करने से इनकार करे मंजूरी दें। यदि कोई संशोधन स्वीकृत किया जाता है, तो अंतिम विकास योजना को संशोधित माना जाएगा। तदनुसार "।

उपरोक्त प्रावधान के एक सादे पठन से यह है -

यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को 156 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2011] 11 एस. सी. आर. से सम्मानित किया गया है। अंतिम विकासकर्ता में मामूली संशोधन करने की शक्ति योजना बनाएँ। इस प्रकार, अधिनियम की योजना के तहत, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत एक विकास योजना अधिनियम का प्रारंभ अंतिम माना जाएगा। अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत प्रदत्त शक्ति। की मंजूरी विकास योजना का मसौदा धारा 31 (1) के तहत प्रदान किया गया है। एक्ट करें।

13. अधिनियम की योजना को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमारी राय है कि द्वारा स्वीकृत विकास योजना अधिनियम के प्रारंभ से पहले राज्य सरकार, अधिनियम के तहत अंतिम विकास योजना बन गई है। शुरू होने से पहले मौजूद विकास योजना अधिनियम से पता चलता है कि विचाराधीन क्षेत्र "खेल के मैदान" के लिए आरक्षित था जिसे अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए "स्कूल और सांस्कृतिक समाज" में संशोधित किया गया था और 25 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना द्वारा "स्कूल और सांस्कृतिक केंद्र" के लिए निर्धारित किया गया। इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति थी कानून। यह रिट याचिकाकर्ता की याचिका है कि निगम ने इसे सूचित किया कि प्रस्तावित विकास योजना में विचाराधीन क्षेत्र इसे "क्रिकेट क्लब और खेल का मैदान" के रूप में दिखाया गया है। हुआ था। 25 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना को अंतिम मंजूरी दी गई थी सरकार। राज्य सरकार को प्रस्तुत मसौदा योजना और 24 तारीख की विकास योजना पर विचार किया गया। अप्रैल, 1992 को मंजूरी दी गई थी। हमारी राय में, यह नहीं है विकास योजना का संशोधन लेकिन अधिनियम की धारा 31 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए इसकी मंजूरी। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने इस पर विचार करके खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया अधिनियम की धारा 37 (2) के तहत विकास योजना की मंजूरी के लिए 10 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना और 24 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा अंतिम

विकास योजना जिसने अपने आदेश को अवैध बना दिया है। यह. यह सामान्य है कि आदेश की वैधता मिग क्रिकेट क्लब v पर निर्भर नहीं करती है। अभिनव सहकार शिक्षा 157 समाज [चंद्रमौली के. आर.। प्रसाद, जे।] आदेश में उल्लिखित खंड। में उल्लिखित गलत प्रावधान आदेश स्वयं आदेश को अमान्य नहीं करता है, यदि यह पाया जाता है कि आदेश किसी अन्य प्रावधान के तहत वैध रूप से पारित किया जा सकता है। लेकिन एक मामले में, वर्तमान की तरह, इसके विपरीत क्या है अधिसूचनाओं में उल्लेख किया गया है कि न्यायालय यह नहीं कह सकता है कि अधिसूचना को अवैध बनाने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया था यदि वास्तव में ऐसी शक्ति मौजूद है।

14. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि भूमि का उपयोगकर्ता होना है और यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा जब तक उपयोगकर्ता में परिवर्तन नहीं होता है तब तक इसमें हस्तक्षेप न करें मनमाना पाया गया। इस प्रक्रिया में निवासियों के प्रतिस्पर्धी दावों और आवश्यकताओं पर विचार करना शामिल है। वर्तमान और भविष्य ताकि उनके जीवन को खुशहाल, स्वस्थ और खुशहाल बनाया जा सके। आरामदायक।

हमारा मानना है कि नगर नियोजन के लिए उच्च स्तर की आवश्यकता है। विशेषज्ञता की डिग्री और यह राज्य के निर्णय पर छोड़ देना सबसे अच्छा

है। सरकार जिसके लिए विशेषज्ञ निकाय की सलाह उपलब्ध है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि शक्ति रही है कानून के अनुसार प्रयोग किया जाता है और इसमें कोई मनमानी नहीं होती है।

15. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है, आक्षेपित उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि, वहाँ होगा लागत के बारे में कोई आदेश न दें।

2007 की याचिका © NO.43:

16. सिविल अपील No.2047 में पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए 2007 में, हम अवमानना याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। अवमानना याचिका खारिज की जाती है।

मामलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवाद न्यायिक अधिकारी परनीत कौर (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।